सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-8 21अप्रैल से 5 मई, 2015 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

बिजली उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन कर केन्द्रीय उर्जा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

बिजली उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन

नई दिल्ली: 7 अप्रैल को विभिन्न राज्यों से आए हुए हज़ारों बिजली उपभोक्ताओं ने यहां धरना-प्रदर्शन किया और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। जन्तर-मन्तर पहुँच कर जुलूस एक जनसभा में तब्दील हो गया। जनसभा को कार्यक्रम के संयोजक और अबेका (ऑल बंगाल इलैक्ट्रीसिटी कंज्यूमर्स एसोसिशन) के अध्यक्ष श्री संजीत विश्वास, एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के केन्द्रीय समीति सदस्य श्री सत्यवान, एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव श्री प्राण शर्मा और अबेका के महासचिव श्री प्रद्युत चौधरी ने सम्बोधित किया। इसी की निरन्तरता में 8 अप्रैल को नई दिल्ली के राजेन्द्र भवन में बिजली उपभोक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से विभिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश श्री राजेन्द्र सच्चर गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके। अपने संदेश में उन्होंने निजीकरण की कड़ी निन्दा की और बिजली उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि बिजली कानून 2003 को खारिज किया जाना चाहिए। इसी के साथ विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, तकनीकीवैत्ताओं और उर्जा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो एक जनहितैषी बिजली कानून का खाका तैयारी करेगी।

विख्यात समाजिक कार्यकर्ता व 'मेनस्ट्रीम' के संपादक सुमित चक्रवर्ती ने अबेका को बिजली की समस्याओं के खिलाफ एक पूर्णतावादी धारणा अख्तियार करने के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि शासक वर्ग नव-उदारवादी नीतियों को लागू कर रहा है और उसके बाद जनता को यह कहकर भ्रमित कर रहा है कि इससे विकास के युग का आरम्भ होगा। परन्तु सवाल यह है कि उनके मन में किसके विकास की बात है–जनता का विकास या कॉरपोरेट घरानों का? उन्होंने बताया कि अपने मंसूबे बांधने के लिए वे फासीवादी हथकण्डे अपना रहे हैं।

जंतर मंतर पर बिजली उपभोक्ताओं की रैली को सम्बोधित करते हुए संजीत विश्वास

वहां उपस्थित लोगों को ए.आई.यू.टी.यू.सी. के अध्यक्ष कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने भी सम्बोधित किया।

ए.आई.के.के.एम.एस. के अध्यक्ष कॉ. सत्यवान, ए.आई.एस.ई.सी. के दिल्ली राज्य संयोजक प्रो. नरेन्द्र शर्मा, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के सचिव मण्डल सदस्य रमेश शर्मा, बिहार के बिजली उपभोक्ता संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ता अशोक कुमार सिंह, यू.पी. से वालेन्दर कटियार, ओडिशा से जयसन बेहरा और गुजरात से तुमुल कटारा आदि वक्ताओं ने सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। अबेका के महासचिव की ओर से बिजली बिल कानून 2003 और संशोधित विधेयक 2014 को रद्द करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव सम्मेलन की शुरूआत में ही रखा गया जो सभी प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से ग्रहण किया गया। अबेका के अध्यक्ष संजीत विश्वास ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और सम्मेलन को एक शानदार रूप से सफल बनाने के लिए सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 के खिलाफ

वामपंथी किसान-खेतमजदूरों का संयुक्त प्रतिवाद

पटना : हाल में जारी किये गये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 के खिलाफ वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एम-एल) लिबरेशन, एसयूसीआई (सी), सीपीआई(एम-एल), अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक(क्रांतिकारी) तथा एमसीपीआई(यू) के किसान व खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में 11 अप्रैल को गांधी मैदान स्थित भगत सिंह चौक पर विशाल धरना दिया और इसके बाद रोष प्रदर्शन किया

महाधरना को संबोधित करते हुए विभिन्न वामपंथी पार्टियों के किसान-खेत मजदूर नेताओं ने कहा कि केन्द्र की भाजपा-नीत कारपोरेट-परस्त सरकार अपने आका देशी-विदेशी पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय निगमों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों से उनकी आजीविका के साधन

(शेष पृष्ठ 5 पर)

पटना में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान संगठनों के कार्यकर्ता

नेताजी के परिवार की निगरानी आश्चर्यजनक नहीं –एसयूसीआई(कम्युनिस्ट)

नेहरू सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार की निगरानी कराये जाने पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉ. प्रभाष घोष ने 11 अप्रैल को जारी बयान में कहा : आजाद भारत में भी महान स्वतन्त्रता सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार की नेहरू सरकार द्वारा निगरानी कराने के जो समाचार छपे हैं वे अत्यंत वेदनादायक होने पर भी हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं हैं क्योंकि भारत के आजादी आन्दोलन में महान क्रांतिकारी नेताजी द्वारा साम्राज्यवाद-विरोधी समझौताहीन संघर्ष की लाइन अपनाने के चलते केवल ब्रिटिश शासक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का समझौतावादी, गाँधीवादी नेतृत्व भी नेताजी को भय की नज़र से देखता था और ये उनके विरोधी थे, इसलिए त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद भी उनको पद त्याग करने के लिए मजबूर किया गया था, फिर उनके समझौताहीन संघर्ष पर अडिग रहने की वजह से उन्हें कांग्रेस से निष्कासित तक किया गया था।

भारतीय जनमानस में नेताजी सर्वोच्च स्थान पर आसीन हैं यह बात जानते हुए ही आजाद भारत की कांग्रेस सरकार के लिए नेताजी का नाम, यहाँ तक कि उनकी याद भी भयभीत करने वाली थी। यह घटना कांग्रेस के दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी चरित्र को ही उजागर करती है।

लेकिन इसे आधार बना कर बीजेपी को सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि बीजेपी के सरपरस्त संगठन आर.एस.एस. ने आजादी आन्दोलन में कोई सकारात्मक भूमिका तो निभाई ही नहीं थी बल्कि उन्होंने भारत की जनता के साम्राज्यवाद-विरोधी आजादी आन्दोलन का विरोध भी किया था। आरएसएस का सिद्धांत हिन्दू राष्ट्रवाद था। नेताजी थे धर्मनिरपेक्षता के प्रवक्ता। हिन्दू राष्ट्रवाद के चिन्तन एवं प्रचार की नेताजी ने कठोर शब्दों में निन्दा की थी। इसलिए नेहरू सरकार के कुकृत्यों का लाभ उठाकर बीजेपी खुद को नेताजी का अनुयायी बताने का जो प्रयास कर रही है वह नितांत ढोंग है।

क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम करने का ढंग कैसा हो

— शिवदास घोष

(गतांक का शेष)

एक और पहलू मुझे बहुत परेशान करता है। वर्तमान स्थिति में दूसरों की गलत और अवसरवादी राजनीति का पर्दाफाश करते हुए, हमारी सही राजनीति को बुलंद करना और जनता की भ्रान्तियों को दूर करना हमारा काम है लेकिन क्या हमारी पार्टी के मुखपत्र का काम इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए सही तरीके से इस दिशा में संचालित हो रहा है? मैं नहीं समझता कि इसे निर्णायक तौर से किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहाँ भी राजनीतिक पहलकदमी की कमी है। प्रचार एक बहुत बड़ी कला है। जब तक कोई अनुभवी क्रान्तिकारी न हो जाए और जब तक क्रान्तिकारी उद्देश्यपूर्णता लगातार दिमाग को प्रेरित न करे, कोई भी अच्छा प्रचारक नहीं हो सकता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाएगा कि कैसे, कब और क्या कहना है। हम सत्य को विकृत नहीं करेंगे, लेकिन सत्य प्रस्तुत करने का तरीका बहुत महत्त्वपूर्ण है। क्रान्तिकारियों को प्रत्येक बात हर जगह, किसी भी समय, बिना किसी उद्देश्य के नहीं कहनी चाहिए। जब एक विशेष बात कहने से आधारभूत सत्य, मूल राजनीति का प्रसार अवरुद्ध होगा–उस समय वह बात हम नहीं कहेंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरे किसी मौके पर हम इसे कहेंगे। यदि कोई खास तौर से इसके बारे मे दर्याफ्त करता है तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक खास अंदाज में और खास समय पर। क्योंकि हमारा उद्देश्य एक विषय की स्पष्ट व्याख्या करना है, हमें चर्चा में केवल उन बिन्दुओं को लाना चाहिए जो कुछ रोशनी डालने में सहायक होंगे और दूसरे की समझदारी बढ़ाने में विषय को और भी सरल और स्पष्टता प्रदान करेंगे। यदि हम स्पष्ट रूप से इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो जिस बुनियादी विषय को हमने प्रतिपादित करना चाहा था वह विभिन्न तथ्यों और बिन्दुओं को बेतरतीब ढंग से ले आने के रुझान की वजह से जटिल हो जाता है। इस प्रकार करने का मायने क्रान्तिकारी राजनीति के सारतत्व को ही नहीं समझना है। यह समस्या नेतृत्व के स्तर तक भी है। यहाँ सिर्फ साधारण कॉमरेडों के बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। नेता जब चर्चा करते हैं तो उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है और रिपोर्ट पेश करने का एक राजनीतिक तरीका होता है। क्रान्ति ही जिनका मकसद है, उन्हें यह समझना चाहिए कि कब, कैसे और क्या कहना है ताकि मुख्य राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने में उसे ज्यादा उपयोगी और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके और यह लोगों का विश्वास अर्जित करने में, विरोधी ताकतों के बारे में जनमानस में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने में हमें सक्षम बना सके। हमें इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए कि वह इस संघर्ष में सहायक न हो। कुछ तथ्यों और बिन्दुओं की उद्देश्यहीन प्रस्तुति ठीक नहीं होती जो सत्य स्थापित करने के रास्ते में इतनी अवरोधक हो जाती है कि आगे बढ़ने की खातिर उसे साफ करना पड़ता है। रिपोर्ट पेश करने और लेख-लिखने का ऐसा उद्देश्यहीन तरीका विकट समस्या है।

लोगों के बीच हमारी पार्टी के बारे में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। गणदाबी (एस.यू.सी.आई.(सी) का बांग्ला मुखपत्र) की बिक्री बढ़ाने के लिए एक बार विशेष अभियान चलाया गया था और बिक्री 27000 तक पहुँच गई थी। अब यह गिरकर 15000 रह गई है, यहाँ तक कि इनको भी न तो तुरन्त बेचा जाता है, न ही बिक्री का पैसा जल्दी आता है। पदाधिकारियों के पास कहने के लिए जवाब है : ''अखबारी कागज के दाम बढ़ गए हैं, पार्टी मुखपत्र की बिक्री का पैसा नियमित नहीं आ रहा है। अत: हम कैसे संभालें? यदि हम इस प्रकार करते रहे तो प्रैस को बन्द करना पड़ेगा।'' क्योंकि अखबारी कागज महंगा हो गया है और कॉमरेड समय पर पैसा जमा नहीं करा रहे हैं और इसलिए प्रैस को बन्द करना पड़ेगा, इसके बारे में क्या किया जा सकता है; यदि 7000 प्रतियों के दाम कल आ जाते हैं, तो हम केवल 7000 प्रतियाँ ही छापेंगे; यदि बिक्री और भी कम होती है तब हम 6000 प्रतियाँ छापेंगे और उसके बाद 3000 प्रतियाँ और इसी प्रकार आगे भी!! क्या पदाधिकारियों का नजरिया यह होना चाहिए? वे मामले को राजनीतिक तौर से नहीं देख रहे हैं : क्यों बिक्री 27000 से घट कर 15000 रह गई है और क्यों 15000 प्रतियों की बिक्री का पैसा भी नियमित रूप से नहीं आ रहा है? जब स्थिति ऐसी है कि लोगों के बीच पार्टी के बारे में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, तब क्यों नहीं मुखपत्र की बिक्री बढ़ जानी चाहिए? पदाधिकारी यदि राजनैतिक तौर पर सोचें तो उनका सरोकार यह होना चाहिए कि कैसे बिक्री बढ़ाई जाए और बिक्री राशि के नियमित आगमन को सुनिश्चित बनाने के लिए क्या किया जाए। इसकी बजाय वे दफ्तर के अफशरशाही ढंग की सोच का शिकार हो रहे हैं। काम करने के इस अफसरशाही तौर-तरीके को तुरन्त बन्द करना होगा। हमें अफसरशाही नेतृत्व की जरूरत नहीं है, हमें राजनीतिक नेतृत्व चाहिए। इस राजनीतिक नेतृत्व को सुधारने के चलते यदि रोजमर्रा के काम में कुछ व्यवधान भी आ जाए, तो आ जाने दो, यद्यपि बेहतर तो यह है कि रोजमर्रा के काम में व्यवधान न आए। वरना पदाधिकारी कहेंगे : ''इस प्रकार तो कोई भी सिस्टम नहीं बचेगा।'' हम काम के सिस्टम को बचाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन यदि मुझे सिस्टम को बरकरार रखने और राजनैतिक नेतृत्व को मजबूत बनाने में से एक को चुनना पड़े तो मैं कहूँगा कि यदि ऐसा ही है तो हमें राजनैतिक नेतृत्व चाहिए और 'सिस्टम' जाए भाड़ में। लेकिन दक्षता की पहचान तो तब है कि जब आप काम के सिस्टम में व्यवधान लाए बिना, राजनैतिक नेतृत्व को लगातार जारी रख सकते हैं।

राजनैतिक नेतृत्व का प्रमुख काम है स्थिति का सही-सही जायजा लेना। हमारी पार्टी की साख बढ़ी है, जनसमर्थन बढ़ा है और पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन हमारे मुखपत्र की बिक्री क्यों घट गई है? क्यों हमारे फैसले सिर्फ इस बात से निर्धारित हों कि बिक्री राशि जमा हो रही है या नहीं? मुझे रिपोर्ट का सही-सही अध्ययन करना चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को यह दिखाना मेरा काम है कि वे कहाँ गलती पर हैं, कहाँ वे चूक कर रहे हैं, कहाँ वे घिसी-पिटी सोच का शिकार बन रहे हैं और क्यों वे एक काम के साथ दूसरे का मेल नहीं बैठा पा रहे हैं। यह सब हमें ही तो करना है। नेताओं को ही तो इन सब मामलों को देखना है। जब वे किसी प्रचार में लगे हैं और उनको चन्दा इकट्ठा करने या एक आन्दोलन को संचालित करने या विभिन्न दूसरे कार्य करने को कहा जाए तो पार्टी कार्यकर्ता नहीं जानते हैं कि कैसे काम के बढ़ते दायरे के साथ-साथ पार्टी साहित्य की बिक्री भी बढ़ाई जा सकती है। वे सोचते हैं कि साहित्य बिक्री का कार्यक्रम उस कार्यक्रम से बिल्कुल भिन्न है जिसके लिए वे वर्तमान में व्यस्त हैं। वे सोचते हैं कि पहले मौजूदा कार्यक्रम पूरा हो जाए तब वे भोजन व आराम करेंगे और उसके बाद पार्टी मुखपत्र बेचने के लिए निकलेंगे। मानो ये दोनों कोई अलग-अलग कार्यक्रम हों। इस तरह जहाँ भी कोई दूसरा कार्यक्रम आ जाता है, मुखपत्र की बिक्री बन्द हो जाती है। लेकिन मुखपत्र तो क्रान्तिकारियों के साथ सदैव रहता है। जहाँ भी वह जाता है मुखपत्र उसके साथ जाता है। प्रत्येक कॉमरेड का नजरिया होना चाहिए: 'जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ और जिस भी आन्दोलन में मैं जुटा हूँ, मैं अपने साथ पार्टी मुखपत्र रखता हूँ और इसे बेचता हूँ।' इसी प्रकार, नेतृत्व को भी मुखपत्र की बिक्री को राजनैतिक रूप से देखना है। एक लोकल यूनिट दलील देती है : 'हम इससे ज्यादा प्रतियाँ नहीं ले सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं।' नेतृत्व पूछता है कि कितनी प्रतियाँ यूनिट ले सकती हैं। यूनिट जवाब देती है: 'सिर्फ इतनी ही।' नेतृत्व कहता है: 'नहीं, तुम्हें ज्यादा प्रतियाँ लेनी चाहिएं।' यूनिट जवाब देती है: 'हम और ज्यादा नहीं ले सकते।' नेतृत्व इसको स्वीकार कर लेता है और कहता है: 'अच्छा, क्योंकि तुम और ज्यादा प्रतियाँ नहीं ले सकते तो इतनी ही सही।' यदि वे कल आकर कहते हैं कि वे कम संख्या लेंगे और बाद में संख्या को और भी कम करना चाहते हैं, नेतृत्व उसको भी स्वीकार कर लेगा! क्या ये राजनीतिक नेतृत्व है? राजनीतिक नेतृत्व का मायने है स्थिति का सही आंकलन। इस बात की जांच करनी होगी की क्या यूनिट जो कहती है, वह स्थिति को सही तरीके से प्रतिबिम्बित करता है। यदि स्थिति वास्तव में ही ऐसी है कि मुखपत्र की बिक्री इस हद तक गिर सकती है, यदि यह मालूम हो जाए कि यूनिट द्वारा लिया गया स्थिति का जायजा सही है और नेतृत्व के जायजे से मेल खाता है, तब बात अलग है। लेकिन जहाँ दो आंकलन मेल नहीं खाते हैं, तब हमें मामले की गहराई से पड़ताल करनी होगी। नेतृत्व को तुरन्त यह पता लगाना होगा कि यूनिट क्यों इस तरह सोच रही है और क्यों यूनिटों द्वारा ली गई मुखपत्र की प्रतियाँ बिन बिके रह जाती हैं। नेतृत्व को बिना जांच किए यूनिट के सुझावों के अनुसार काम नहीं करना है। वरना केन्द्रीयता का कोई मायना नहीं है, नेतृत्व का कोई मायना नहीं है। वर्तमान में क्या चल रहा है? औसत जनवाद, यानी कि यूनिट जो सुझाव दे उसके अनुसार चलना–लगभग ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है। यूनिटों की बात पर ध्यान देने की अवधारणा और नेतृत्व को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझावों को लेने की बात को, यूनिटों के पिछलग्गू बनने के स्तर तक गिरा दिया गया है। यह नहीं चल सकता है। यूनिटों के घिसे-पिटे विचार, उनकी कमजोरियों और कमियों की बारीकी से पड़ताल करनी होगी। सभी स्तरों पर यह करने की क्षमता नेतृत्व को अर्जित करनी होगी। राज्य, जिला और स्थानीय–सभी स्तरों पर इस अभ्यास को निष्ठा के रूप में आगे बढ़ाना है। जहाँ कहीं भी कमियाँ हैं, उनकी आलोचना होनी चाहिए, आरोप लगाने के नजरिए से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए। ऐसी आलोचनाओं के सामने कोई जैसे भी हो महज अपनी सफाई देने की गरज से कोई बात नहीं रखेगा। क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है, इसके लिए उसे दूसरों पर प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करना एक क्रान्तिकारी के लिए अनैतिक है। इससे अनुशासन का ही सिर्फ उल्लंघन नहीं होता है बल्कि बुनियादी सवाल भी यहाँ खड़ा हो जाता है। क्योंकि कोई किसी असुविधा से रूबरू है, कोई मुश्किल में है महज इसीलिए वह दूसरों की आलोचना नहीं कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि किसी बात के लिए उस पर आरोप लगाया गया है उसी समय उसे प्रत्यारोप नहीं लगा देना चाहिए, चाहे उसके प्रत्यारोप में कुछ सत्य ही क्यों न हो, इसको किसी दूसरे समय करना चाहिए, जब वह निर्वैयक्तिक रूप से आएगा। प्रत्यारोप को बचाव के लिए तर्क के रूप में पेश करना, क्योंकि उसकी आलोचना की गई है, एक क्रान्तिकारी के लिए अनैतिक है। ये बातें एक अच्छे क्रान्तिकारी कैडर के विकास के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

नारा उठाइए कि, ''हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना है।'' प्रत्येक कॉमरेड को इस बारे में चौकस होना चाहिए कि उसके काम करने के तरीके में सुधार हो रहा है या नहीं, हमारे सामूहिक रूप से काम करने के तरीके में सुधार हो रहा है या नहीं–सुधार इस मायने में कि यह हमारे अन्दर तेजी और उत्साह पैदा कर रहा है। हमें सब की क्रियाशीलता को बढ़ाने, हमारी काम करने की क्षमता और राजनीतिक पहलकदमी को बढ़ाने, हमारी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने, हमारे जनसम्पर्क और पार्टी साहित्य की बिक्री बढ़ाने को ध्यान में रख कर ही काम करने के तरीके को सुधारना है। पार्टी प्रकाशन हमेशा हमारे साथ रहने चाहिएं ताकि किसी के साथ एक चर्चा के बाद उसे हम एक विशेष प्रकाशन जिसे हम सबसे उपयुक्त समझते हों तुरंत मुहैया करा सकें; और बाद में हमें दूसरे कॉमरेड से अनुरोध नहीं करना पड़ता है, ''कृपया अमुक घर में चले जाओ और उसको हमारे फलां प्रकाशन की एक प्रति दे आओ।'' क्योंकि इस प्रकार की आदत बहुत नुकसान करती है। एक तो, जिस कॉमरेड से आपने अनुरोध किया है, बाद में वह इसे भूल जा सकता है। दूसरे, यदि आप उस कॉमरेड को नोट भी करा देते हैं कि एक खास प्रकाशन फलां आदमी को पहुँचाना है, वह इसे नोट भी कर लेता है, लेकिन इस जिम्मेदारी को किसी दूसरे को सौंप देता है, जो फिर आगे और किसी दूसरे पर इस जिम्मेदारी को डाल देता है। इस प्रकार, स्तर दर स्तर सूप बासी होता रहता है, अखबार वांछित जगह पर नहीं पहुँचता है। ये

(शेष पृष्ठ 4 पर)

देश भर में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल का विरोध

पटना : देश भर में हो रहे विरोध तथा राज्यसभा में पारित न होने की स्थिति में देश के किसानों के हित को पूरी तरह से दरकिनार कर हाल में जारी किये गये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 के खिलाफ 6 अप्रैल को छः वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीआई(एम), एसयूसीआई(सी), सीपीआई(एम-एल), अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक(क्रांतिकारी) तथा एमसीपीआई(यू) के किसान-खेतमजदूर संगठनों द्वारा संयुक्त प्रतिवाद किया गया और गांधी मैदान स्थित भगत सिंह चौक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान वामपंथी कार्यकर्ताओं ने झंडे-बैनरों के साथ भाजपा नीत केन्द्र सरकार को किसान व खेत मजदूर विरोधी बताते हुए जमकर नारे लगाये।

इसके बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने आम जनों से, खासकर किसान व खेत मजदूरों से इस जनविरोधी अध्यादेश के खिलाफ ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

सभा को सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सदस्य जानकी पासवान व बिहार राज्य किसान सभा के सचिव अशोक प्रसाद सिंह, सीपीआई(एम) के राज्य सचिव अवधेश कुमार व अरूण कुमार मिश्र, एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव शिव शंकर व अरूण कुमार सिंह, एमसीपीआई(यू) के राज्य सचिव विजय कुमार चौधरी, सीपीआई(एम-एल) के अरविन्द सिन्हा तथा अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक के बाल गोविन्द सिंह ने संबोधित किया।

जोया (अमरोहा) : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आगामी 5 मई को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन की सफलता हेतु सरकड़ी अजीज गाँव में ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन की एक सभा चन्द्रपाल सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सभा की शुरूआत संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष का. शील कुमार ने अपने गीत 'मेहनतकश भाइयों आई मुसीबत भारी' से शुरु की।

संगठन के प्रदेश सचिव कॉ. जगन्नाथ वर्मा ने केन्द्र सरकार की किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 आजाद भारत का सबसे क्रूर एवं घिनौना कारनामा है। इससे देश के करोड़ो किसानों, भूमिहीन खेत मजदूरों व पशुपालकों की पीढ़ी की रोजी-रोटी उजड़ जायेगी। इस देश के किसानों के साथ एक साजिश रची जा रही है । सभी सरकारें किसान-मजदूर विरोधी हैं। सरदार राजेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शन की सफलता के लिए हमें एकजुट होकर दिल्ली पहुँचना है। संचालन कॉ. दिगराज सिंह ने किया। सभा में महेन्द्र सिंह, पवन कुमार, इलियास अली, सुजीत सिंह, मूलचन्द, कृपाल सिंह, टेकचन्द, पीलू सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

भिवानी : ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन की ओर से 4 अप्रैल का तोशाम और 6 अप्रैल को भिवानी में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रतियां जला कर इसके खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। संगठन का प्रतिनिधिमण्डल तहसीलदार से मिला और उनकी मार्फत मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। बेमौसमी बारिश, तेज आंधी व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का 30 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने, प्रभावितों के कृषि ऋण माफ करने, कृषि भूमि अधिग्रहण पर मुकम्मल रोक लगाने, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल वापस लेने, हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार देने, सभी फसलों के लाभकारी दाम देने, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दाम आधे करने,यूरिया खाद कोऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने और आवारा पशुओं का प्रबंध करने की मांग की गई। ज्ञापन देने गये प्रतिनिधिमण्डल में संगठन के जिला प्रधान कॉ. जिले सिंह और जिला सचिव रोहताश सेनी, फूलसिंह, हवासिंह, जयबीर आदि किसान नेता शामिल थे। 6 अप्रैल को झज्जर, सोनीपत, रेवाड़ी, नारनौल, कैथल आदि जिलों में भी किसानों ने धरने-प्रदर्शन किये गये और अध्यादेश की प्रतियां फूंकी गई।

सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ आंदोलन तेज करने के संकल्प के साथ
''सेमेस्टर हटाओ यात्रा'' का समापन

भोपाल : मध्य प्रदेश के 16 जिलों व 6 विश्वविद्यालयों में जाकर छात्र संगठन ऑल इंडिया डी.एस.ओ ने 'सेमेस्टर हटाओ यात्रा'' निकाली और छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों को लामबंद किया। 23 से 27 मार्च तक द्वितीय चरण में ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, दतिया आदि जिलों में यात्रा पहुँची। ग्वालियर के के.आर.जी. गर्ल्स कॉलेज से साइकिल यात्रा शहर के विभिन्न कॉलेजों में पहुँची। 23 मार्च को शहीद भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु की याद में सभा की गई। जीवाजी विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन कर कुलपति को सेमेस्टर प्रणाली वापिस लेने की मांग पर ज्ञापन दिया गया। 30-31 मार्च को तृतीय चरण में यात्रा जबलपुर के विभिन्न कॉलेजों व रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी पहुँची। 6 से 10 अप्रैल तक अंतिम चरण में सागर, विदिशा, सीहोर जिलों व भोपाल के विभिन्न कॉलेजों व बरकाउत्तला वि. वि. में यात्रा पहुँची। शुरूआत सागर से हुई। यात्रा सागर के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय भी पहुँची।

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. अशोक मिश्रा

समापन 10 अप्रैल को प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एक विशाल प्रदर्शन के साथ हुआ।

सभा को संबोधित करते हुए ए.आई.डी.एस.ओ. के अखिल भारतीय महासचिव कॉ. अशोक मिश्रा ने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली छात्रों को व्यक्ति केंद्रित बना रही जिससे वे सामाजिक समस्याओं के बारे में नहीं सोच पा रहे है। सेमेस्टर प्रणाली व उसके साथ लाई गई ग्रेडिंग और ताजातरीन सीबीसीएस सिस्टम शिक्षा के सारतत्व को खत्म करने की शासक पूंजीपति वर्ग की सोची-समझी चाल है। पूँजीपतियों के इशारे पर चलने वाली केन्द्र व राज्य सरकारें गैर जनवादी ढंग से छात्रों के जनवादी अधिकार छीनती जा रही हैं। सेमेस्टर प्रणाली व अन्य शिक्षा-विरोधी नीतियों को थोपा जा रहा है। सभा को अखिल भारतीय काउंसिल सदस्य विनोद लोगरिया, अजीत सिंह पवार, श्रुति शिवहरे, नित्या, कंचना ने भी संबोधित किया। एसयूसीआई(सी) मध्य प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य कॉ. सुनील गोपाल सहित सभी वक्ताओं ने सेमेस्टर प्रणाली के दुष्परिणाम व शिक्षा क्षेत्र में पूंजीनिवेश की खिलाफत की। अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य कॉ. मुदित भट्नागर ने इसका संचालन किया। सभा अध्यक्ष अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य कॉ. सचिन जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई से बने प्रदेश के 1 लाख 21 हजार सरकारी स्कूलों को पूंजीपतियों को ठेके पर देने की बात कही है जिससे प्रदेश के करोड़ों छात्र व लाखों शिक्षकों का भविष्य संकट में है। उन्होंने पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूल-कॉलेज बचाओ-शिक्षा बचाओ आंदोलन चलाने के लिए आह्वान किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया।

किशनगंज में महिला सम्मेलन

दिल्ली : महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों, शराबखोरी व अश्लीलता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एआईएमएसएस द्वारा 24 मार्च को किशनगंज इलाके में महिला सम्मेलन किया गया। इसमें महिलाओं पर बढ़ते अपराधों तथा समाज में हो रहे नैतिक-सांस्कृतिक पतन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें मुख्य वक्ता थे एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. के.सी. तिवारी। ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य अध्यक्ष प्रो. सुबोध शर्मा, उपाध्यक्ष एडवोकेट दीपिका जैन, सचिव रितु कौशिक, सचिवमण्डल सदस्य श्रीमती सीता सिंह ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती आशा रानी ने की। सम्मेलन में 13 सदस्यीय समिति चुनी गई जिसमें ओमवती को अध्यक्ष, रितु गिरि व बबीता को उपाध्यक्ष तथा सीमा चौहान को सचिव चुना गया। संगठन द्वारा दिल्ली के अन्य इलाको जैसे सोनिया विहार, बुराड़ी, साकेत, भलस्वा, बृज विहार आदि में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएं की गई। इनको संगठन की पुष्पा चमोली, एडवोकेट दीपिका जैन, रितु कौशिक, सीता सिंह व आशा रानी ने संबोधित किया।

केनया विश्वविद्यालय में छात्रों के बर्बर हत्याकाण्ड पर जताया शोक

हैदराबाद : केनया विश्वविद्यालय में 147 छात्रों के बर्बर हत्याकाण्ड के विरुद्ध ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की हैदराबाद जिला कमेटी की ओर से यहां कैण्डिल लाइट जुलूस निकाला गया। ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. आंध्र प्रदेश राज्य सचिव कॉ. गंगाधर इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। हैदराबाद के जिला अध्यक्ष कॉ. डी. गंगाजी, हैदराबाद जिला सचिव कॉ. मल्लेश राज के अलावा अनेक छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

अपने वक्तव्य में कॉ. गंगाधर ने केनया विश्वविद्यालय में हुए इस भयंकर हत्याकाण्ड की कड़ी निन्दा की। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद और रूढ़िवाद के सरपरस्त साम्राज्यवादी हैं। उन्होंने समाज के विवेकशील और शान्तिप्रिय लोगों से साम्प्रदायिकता, रूढ़िवाद का एकताबद्ध होकर विरोध करने और हर प्रकार की विषमताओं एवं भ्रम-भ्रान्तियों को दूर करने की अपील की।

क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम!!

(पृष्ठ 2 का शेष)

तमाम खराब बातें हैं। लटकने वाले थैले लेकर जो चलते हैं, वे आसानी से पार्टी साहित्य अपने साथ में ले जा सकते हैं। इस प्रकार चलने में हर्ज क्या है? जन संगठनों और यूनिटों में जो काम करते हैं और लोगों के साथ मिलते हैं उन सब को हमेशा लटकने वाला थैला लेकर चलना चाहिए। इन थैलों में पुस्तिकाएं, पार्टी मुखपत्र की प्रतियाँ, दस्तावेज, रसीद बुक कमोबेश वह सब होना चाहिए, जिसकी जरूरत पड़ सकती है। जब किसी को 'सांस्कृतिक स्तर का पतन और बेकारी की समस्या का समाधान किस रास्ते' पुस्तिका की एक प्रति देने की जरूरत हो तो हम इस पुस्तिका की एक प्रति बैग से निकाल कर उस आदमी को दे सकते हैं। यदि बातचीत के दौरान भारत-सोवियत संधि का सवाल उठ खड़ा हो तो हम मुखपत्र का पुराना अंक निकाल कर दे सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान इस संधि के बारे में हमने जो कहा था, वह छपा है। लेकिन समस्या यह है कि कॉमरेड इस बात की खोज खबर ही नहीं रखते हैं कि कौन से अंक में क्या छपा है, क्योंकि वे उनको पढ़ते ही नहीं हैं। आधे से भी ज्यादा कॉमरेड अपने खुद के प्रकाशनों को भी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो कार्यकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं और जनता में सक्रिय रूप से काम करते हैं, वे भी आमतौर पर इन साहित्यों का अच्छी तरह अध्ययन नहीं करते हैं, न ही वे आपस में इस बारे में चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। इसलिए वे कैसे जान पाएंगे की कौन सा महत्त्वपूर्ण लेख किस मुखपत्र के किस अंक में छपा है? इसलिए नेताओं को नजर रखनी होगी कि कॉमरेड नियमित रूप से पार्टी साहित्य पढ़ रहे हैं, वे उसे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में रूटीन सर्कुलरों के माध्यम से यूनिटों को सूचित करना ही काफी नहीं है। जब भी कभी नेतागण कॉमरेडों से गपशप करें या उनसे बात करें, उन्हें समय-समय पर इन सब के बारे में दर्याफ्त करनी चाहिए। ''क्या आपने मुखपत्र का यह अंक पढ़ा है? क्या आप उस लेख को समझ सके हैं? क्या आपने मुखपत्र का वर्तमान अंक बेचा है? क्या मुखपत्र की बिक्री बढ़ रही है? क्या आप इसकी बिक्री के पैसे को नियमित रूप से जमा करा रहे हैं?''– आन्दोलनों के बारे में विभिन्न बातों और चर्चाओं के बीच भी इन सब बातों की दर्याफ्त करनी चाहिए। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तमाम कामों के बीच नेताओं को इसका प्रयास करना चाहिए। जब ट्रेड यूनियन द्वारा कोई हड़ताल की जा रही हो, छात्र-युवा मोर्चे का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा हो, यहाँ तक कि जब हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा हो– तब भी तमाम कार्यकलापों के बीच में ये सब पूछताछ करनी है। कॉमरेडों के साथ तमाम विभिन्न चर्चाएं करते हुए भी इन सब बिन्दुओं की पड़ताल करनी है। यह है जिसे मैं कहता हूँ नेताओं का सही राजनीतिक आचरण, नेताओं के अस्तित्व का सही राजनीतिक ढंग। इसके बिना, नेताओं के काम करने का तरीका रूटीन अफसरशाही तरह का हो जाएगा। बस दफ्तर में आना और वापस चले जाना, सर्कुलर जारी करना, इस या उस कॉमरेड को निर्देश देना, मीटिंग बुलाना, इस या उस कॉमरेड को नोट करवाना, कुछ पत्रों को पढ़ना और कुछ एक का जवाब देना। क्या यह राजनीतिक काम है? इतना तो एक क्लर्क भी कर सकता है। नहीं, नेता का काम करने सही ढंग ऐसा नहीं होता है। नेताओं को भी ऐसे टैक्नीकल काम करने पड़ते हैं। ये सब जरूरी बुराइयाँ हैं। ये काम करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इनसे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन इनकी वजह से बहुत सा समय बर्बाद होता है। यह अच्छा होता, यदि कॉमरेडों को राजनीतिक तौर से लैस करने के लिए कुछ ज्यादा समय उपलब्ध होता।

क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तौर से लैस करने का तरीका केवल एक ही है? क्या सभाएं और व्यक्तिगत बातें ही एकमात्र तरीका है? नहीं, इसको जाहिरा तौर पर बेकार लगने वाली बातों के माध्यम से भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन अवश्य ही, हमें यह जानना होगा कि कैसे बातचीत या गपशप इस तरीके से की जाए कि राजनीति के बारे में एक शब्द भी बोले बिना कॉमरेडों को ढाला जा सके और केवल उनके साथ मिलने-जुलने और हंसी मजाक के माध्यम से भी उनके मानसिक गठन को परिवर्तित किया जा सके। यह क्षमता स्वत:स्फूर्त नहीं आ जाती है, इसे सीखना पड़ता है। इसको हासिल करने की मुख्य पूर्वशर्त क्या है? यह है कि क्रान्ति मेरे खून में समा गई है। क्रान्ति के सामने दूसरी हर चीज अशुद्ध होने के नाते गौण है और इसीलिए उनमें इतनी शक्ति नहीं कि मेरी क्रान्तिकारी चेतना और पहलकदमी में व्यवधान पैदा कर सकें। यदि वे शक्ति अर्जित कर लें और सर उठाने का प्रयास करें तो मेरे अन्दर की क्रान्तिकारी शक्ति इसको रोकती है और नहीं होने देती है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरीके से अपने निर्माण का प्रयास करना चाहिए। अब हमारा नारा होना चाहिए : स्थिति का मुकाबला करो, कार्यशैली को सुधारने के लिए अपने आप को तैयार करो, अपनी राजनीतिक चेतना और पहलकदमी को बढ़ाओ, अपने मुखपत्र और साहित्य का नियमित अध्ययन करो, अपने मुखपत्र के वितरण को बढ़ाओ, लोगों के पास जाओ, जनसंघर्ष गठित करो और संगठन को बढ़ाओ। अब मुख्य कार्य यही हैं।

जिन बुनियादी कमजोरियों से हम ग्रस्त हैं उनसे तथा जिन कमजोरियों की वजह से हम अपनी पूरी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उनसे यदि छुटकारा पा सकें, तो हम वर्तमान स्थिति का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अभी तो, अपने देश की विशालता को देखते हुए, हमारे पास आवश्यक संसाधन भी नहीं हैं। हम बहुत पीछे हैं और काफी अरसे तक हमारे लिए इस प्रकार की शक्ति अर्जित करना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ से देखने पर, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिस प्रकार लोगों की जुझारू मानसिकता उजागर हो रही है, जिस तरीके से हमारी पार्टी के बारे में लोगों की जिज्ञासा ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है–ऐसी स्थिति में, हमारा प्रसार काफी हद तक तेज होगा यदि हमारे कार्यकर्ता अपने सीमित संसाधनों और शक्ति का उचित इस्तेमाल करने के लिए अपनी राजनीतिक चेतना और कार्यशैली को उन्नत करते हैं, चर्चा-बहस संचालित करने की कला में निपुणता हासिल करते हैं और अपने मुखपत्र के वितरण को बढ़ाते हैं। लोगों के सामने व्याख्या करनी है कि वे यह समझ जाएं कि पूँजीवाद शत्रु है और इसको उखाड़ फेंकना है। ग्रामीण और औद्योगिक सर्वहारा, अर्ध-सर्वहारा के साथ मिलकर इसे उखाड़ेंगे और इस संघर्ष में विजय, नकली मार्क्सवादियों को जनता से सफलतापूर्वक अलग-थलग करने पर ही निर्भर करती है। इस बात को सुनिश्चित करना है कि कॉमरेड अपनी पार्टी की राजनीति और परिस्थिति को ठीक ढंग से समझते हैं, इसके अनुरूप ही लाइन पर रोशनी डालते हुए वे लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। यदि कोई पूँजीवाद के खिलाफ केवल भाषण देता है, क्रान्ति में सर्वहारा की भूमिका की व्याख्या करता है या कांग्रेस की काली करतूतों को मात्र सूचीबद्ध कर देता है–तो क्या एक संपूर्ण राजनीतिक भाषण हो जाता है। नहीं, तमाम समस्याओं के साथ मुद्दे को जोड़ कर यह दिखाना होगा कि पूँजीवाद को उखाड़ फेंकना क्यों जरूरी है। इस बात की सही प्रकार से व्याख्या करनी होगी कि क्यों मजदूर वर्ग ही इस सर्वहारा क्रान्ति को नेतृत्व प्रदान करेगा, इसके मित्र कौन होंगे और किस प्रकार उन्हें इस लड़ाई को संचालित करना होगा? मजदूर वर्ग विजय हासिल कब करेगा? केवल तभी जब वह नकली क्रान्तिकारियों के बारे में भ्रम से मुक्त होकर सही क्रान्तिकारी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। केवल तभी जब क्रान्तिकारी पार्टी, नकली-क्रान्तिकारियों को बेनकाब करने और संयुक्त संघर्ष में उनके साथ काम करते हुए भी उनको परास्त करने में सक्षम होगी। इसलिए जब तक उनका पर्दाफाश नहीं हो जाता है और उन्हें लोगों से अलग-थलग नहीं कर दिया जाता है तथा उनके बारे में भ्रम बरकरार है, उनको संयुक्त संघर्ष में खींच लाना होगा। जब तक ये संयुक्त संघर्ष की प्रमुख शक्ति हैं, क्रान्तिकारी आन्दोलन के सामने मुख्य बाधा भी यही है। इन आधारभूत बातों की समझ हासिल करना ही असल राजनीतिक समझदारी है, इनको विश्वासोत्पादक व सुबोधगम्य ढंग से एक भाषण में रखने से ही एक असल राजनीतिक भाषण बनता है।

तमाम नेता-कार्यकर्ताओं को बिना समय गवांए अपने स्तर को एक पर्याप्त दर्जे तक ऊपर उठाना होगा ताकि उनका दैनिक कार्य, लेखन, चर्चाएं और भाषण सही राजनीतिक विचार और वर्ग चेतना को प्रतिबिम्बित कर सकें। केवल तभी हम, जो भी हमारी शक्ति है, उसको एकजुट करते हुए अपनी गति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। शायद हम उसे संभव बना सकते हैं जो अभी असंभव प्रतीत होता है यानी हम जनता के बीच हमारी पार्टी के बारे में बढ़ती रुचि और उनकी बढ़ती संघर्षमुखी मानसिकता को ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हुए प्रभावशाली ढंग से अगुआ भूमिका हासिल करने को संभव बना सकते हैं। हम सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से ही नहीं बल्कि प्रभावशाली ढंग से परिस्थिति को संभालने, गाइड करने और प्रभावित करने की क्षमता अर्जित कर सकते हैं। केवल तभी, भारत में एक प्रभावशाली क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ क्रान्ति की वस्तुस्थिति पहले से ही मौजूद है। इसके लिए यांत्रिक कार्यप्रणाली की गहरी पैठी हुई आदत और काम से बचने के बहाने खोजने के रुझान को हमें दूर करना होगा। जब कोई वास्तविक मुश्किल हो तब अवश्य ही, हमें धैर्यपूर्वक सुनना होगा। लेकिन जब मनगढ़ंत मुश्किल के आधार पर खोखला बहाना पेश किया जाए, तो हमें इसे पकड़ पाने में सक्षम होना चाहिए। जिस प्रकार हमें एक असल बिन्दु पर ध्यान देना चाहिए, वैसे ही हमें नकली बहानों के खिलाफ लड़ना चाहिए जो भ्रान्ति पैदा करने के लिए असल के रूप में उभर कर आते हैं और काम की पहलकदमी में रुकावट पैदा करते हैं। राजनीतिक चर्चा को प्रोत्साहित करना है, लेकिन उद्देश्यहीन राजनैतिक चर्चा को नहीं, बल्कि वे राजनैतिक चर्चाएं जो पार्टी की मूल राजनीतिक लाइन से आती हैं, प्रोत्साहित करनी चाहिएं लेकिन किसी भी अनुभववादी या पण्डिताऊ चर्चा को नहीं, जो उद्देश्यपूर्ण नहीं है।

रिकार्डों को सुरक्षित रखना सम्पादक मण्डल का एक महत्त्वपूर्ण काम हैं। स्टेट कमेटी को इसकी देखभाल करनी है। कमेटी को यह देखना चाहिए कि मुखपत्र केवल नियमित रूप से प्रकाशित ही नहीं होते हैं बल्कि लेखन का स्तर भी लगातार सुधरता जा रहा है। इसके लिए, सम्पादक मण्डल को इसे एक गम्भीर जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए और लगातार अध्ययन, विश्लेषण, चर्चाएं, लेखन करना और दूसरी पत्रिकाओं का अध्ययन करते हुए सामग्री एकत्र करना व उनसे नोट्स बनाने चाहिएं। जो इसमें संलग्न होंगे उन्हें अपने लेखन की शैली को सुधारना चाहिए। यह आदत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे अखबारों व मैगजीनों को मात्र पढ़ा और फिर उन्हें एक तरफ रख दिया। संपादक मण्डल के अध्ययन का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका काम है विभिन्न सूचनाओं और डाटा द्वारा नेतृत्व को जानकारियाँ प्रदान करते रहना। उनके पढ़ने के तरीके में सुधार की जरूरत है। उन्हें कागज-पैंसिल अपने पास रखनी चाहिए और किसी भी सूचना या बिन्दु को जिसे वे संदर्भ के लिए उपयोगी समझते हैं, दिनांक सहित तुरन्त नोट कर लेना चाहिए। हो सकता है उसकी जरूरत अभी न हो, लेकिन बाद में कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है और उनको इस सामग्री को सावधानीपूर्वक सहेज कर रखना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े पार्टी इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन न तो हमारे सम्पादक मण्डल के सदस्य और न ही कॉमरेड इस तरीके से अध्ययन करते हैं। इसलिए वे लैस नहीं हो पाते हैं। मात्र एक जटिल लेख या राजनीतिक विश्लेषण से काम नहीं बनेगा। कुछ ठोस डाटा और जानकारियाँ इनमें देने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि उस समय आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध नहीं होती है तथा उसको तलाशना पड़ता है और इस प्रकार लेख में देरी हो जाती है। या नहीं तो कोई अपनी याददाश्त से बताता है कि उसने एक अखबार एक खास स्थान पर देखा था लेकिन वह वहाँ नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि यहाँ भी कार्यशैली को सुधारना चाहिए।

कल कुछ दूर तक मैने चर्चा की थी कि हाल ही में हुई रेलवे हड़ताल (मई 1974 में हुई ऐतिहासिक अखिल भारतीय रेल हड़ताल) ने स्पष्ट तौर से इस तथ्य को पुख्ता कर दिया है कि देश में जनवादी आन्दोलन को

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉरपोरेट-परस्त, जन-विरोधी मोदी सरकार तथा केरल राज्य की भ्रष्ट यूडीएफ सरकार के खिलाफ

एसयूसीआई(सी) ने दिया सचिवालय पर धरना

त्रिवेन्द्रम : एस.यू.सी.आई.(सी) केरल राज्य कमेटी के तत्त्वावधान में लगभग 2000 लोगों ने 10 अप्रैल को सचिवालय पर धरना और राजभवन तक मार्च में हिस्सा लिया। नितांत जनविरोधी केन्द्र व राज्य बजटों को वापस लेने, भूमि अधिग्रहण कानून के किसान-विरोधी संशोधन रद्द करने, श्रम कानूनों में मजदूर-विरोधी संशोधनों को रद्द करने, शिक्षा-संस्कृति का साम्प्रदायीकरण बन्द करने, दवाइयों के दाम नियंत्रित करने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट के अनुपात में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम करने आदि 25 ज्वलंत मांगों पर आवाज बुलंद की गई।

महीने भर चले अभियान का समापन सचिवाल्य के सामने धरने से हुआ जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोग सुबह से ही जुटने लगे थे। धरने का उद्घाटन पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य व केरल राज्य सचिव कॉमरेड सी.के. लुकोस ने किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर तक संघर्ष कमेटियों में संगठित हो जाएं ताकि केन्द्र व राज्य की कॉरपोरेट-परस्त जनविरोधी सरकारों के हमलों का प्रतिरोध करते हुए जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए दीर्घस्थाई आन्दोलन किया जा सके।

धरने की अध्यक्षता एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) केरल राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड वी. वेणुगोपाल ने की। धरने को आरएमपी के राज्य सचिव कॉ. एन. वेणु, एस.यू.सी.आई.(सी) राज्य सचिवमण्डल सदस्य, जी.एस. पद्मकुमार, एआईयूटीयूसी राज्य सचिव वी.के. सदानन्दन, एआईडीवाईओ राज्याध्यक्ष टी. के. सुधीर कुमार, एआईएमएसएस राज्य सचिव शयला के. जोन और एआईडीएसओ राज्याध्यक्ष ई.एन. शांतिराज ने सम्बोधित किया। धरने के बाद सुव्यवस्थित और औजपूर्ण जुलूस राजभवन की तरफ बढ़ा जिसे राजभवन के पास रोक दिया गया। वहीं पर एक जनसभा हुई जिसे एसयूसीआई(सी) राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड जेसन जोसेफ और एमसीपीआई(यू) के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड श्रीनिवास दास ने सम्बोधित किया। 25 मांगों के समर्थन में जोरदार नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

7वाँ बिहार राज्य छात्र सम्मेलन सम्पन्न

पटना : 8वीं कक्षा तक पास-फेल प्रथा पुनः लागू करने, सेमेस्टर सिस्टम, शुल्क वृद्धि, एनएएसी, शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण व साम्प्रदायीकरण पर रोक लगाने आदि छात्रों के ज्वलंत मुद्दों पर ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. के तत्वावधान में 7वाँ बिहार राज्य छात्र सम्मेलन 26-27 मार्च को यहाँ संपन्न हुआ। सम्मेलन के खुले सत्र से पहले विभिन्न जिलों से आए छात्र-छात्राओं का जुलूस लंगट सिंह कॉलेज से निकलकर एंव कलमबाग चौक, मोतीझील ओवरब्रिज होते हुए वी.वी. कॉलेजिएट स्कूल पहुँचकर सभा में तब्दील हो गया।

शिक्षा की अधोगति को उजागर करते हुए सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष लंगट सिंह कॉलेज के रसायन शास्त्र के सेवानिवृत प्राध्यापक राम किशोर प्रसाद ने कहा कि किसी समय छात्र देश के कोने-कोने से बिहार आते थे। लेकिन दुर्गत आज यह है कि छात्र मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए नकल करने को विवश हैं। उन्होंने स्कूल-कॉलेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी पर प्रश्न उठाया। उन्होने ने कहा कि आज सरकार विज्ञान के जमाने में भी अंधविश्वास जनित पाठ्यक्रम ज्योतिषशास्त्र आदि पढ़ाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। सभा को डॉ. विजय कुमार जायसवाल, डॉ. अरूण कुमार सिंह, डॉ. मोती प्रसाद सिंह, डॉ. नंदकिशोर नंदन, डॉ. चितरंजन कुमार ने भी सम्बोधित किया।

सभा के मुख्य वक्ता संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक मिश्रा ने कहा कि हर आम और खास आदमी चाहे वह रिक्शा चलाने वाला या मजदूरी करने वाला हो, अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहता है। एक इन्सान बनाना चाहता है। लेकिन वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकारें जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा को धत्ता बताते हुए शिक्षा बजट मे कटौती कर रही हैं। दूसरी तरफ, जनता

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉ. अशोक मिश्रा

पर 3% अतिरिक्त उपकर(सैस) लगाकर धन उगाह रही हैं और इस धन का इस्तेमाल बड़े-बड़े पूँजीपतियों के लिए कर रही हैं। यहाँ की सरकारें नग्न तरीके से पूँजीपतियों की पक्षधर होकर बजट में कटौती कर रही हैं, शुल्क वृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं, निजीकरण व व्यापारीकरण की बाढ़ ला रही हैं। छात्र आन्दोलन न हो इसलिए छात्र राजनीति पर रोक लगा रही हैं। ऐसे में ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. ही एकमात्र छात्र संगठन है जो इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं की रोशनी में उच्च नीति-नैतिकता के आधार छात्रों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आन्दोलनरत है।

प्रतिनिधि सत्र को सम्बोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि केन्द्र सरकार आज शिक्षा पर भीषण हमला कर रही है। घोर फासीवादी तरीके से अवैज्ञानिक, अंधविश्वासजनित मानसिकता तैयार करने की साजिश रच रही है। ऐसे में ऑल इंडिया डीएसओ राज्य कमेटी की नवनिर्मित कमेटी के ऊपर एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि इस समस्या के खिलाफ जुझारू छात्र आंदोलन निर्मित करें। ऑल इंडिया डी.एस.ओ. के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वप्न चटर्जी ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। कॉ. शिवदास घोष पर रचित गान के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

फीस वृद्धि का विरोध

वदोदरा, 13 अप्रैल : ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. ने एम.एस. विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। फीस वृद्धि के निर्णय का विरोध किया गया। एम.एस.यूनिवर्सिटी के अधिकारी लगातार पिछले 4 साल से फीस वृद्धि कर रहे हैं। इस पाँचवें साल में अधिकारी 5वीं बार फीस वृद्धि करने जा रहे हैं। सभी कोर्सों में की गई फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. ने की। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न संकायों और विभागों के छात्रों ने भाग लिया।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 के खिलाफ... पृष्ठ 1 का शेष

जमीन को छीन कर उन्हें बर्बाद करने पर उतारू है। सेज के लिए अधिग्रहित की गयी बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। उस पर कोई उद्योग नहीं लगा। रीयल एस्टेट के कारोबारी पूंजीपतियों के मुनाफे को और बढ़ाना ही इसका मकसद है। वक्ताओं ने कहा कि जमीन के साथ जुड़े किसान-खेत मजदूरों के किसी किस्म के पुनर्वास की बात अध्यादेश में नहीं है। पूर्ववर्ती कानून में जमीन के अधिग्रहण के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के लिए 70 फीसदी और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 80 फीसदी जमीन के मालिकों की मंजूरी अनिवार्य थी। मौजूदा अध्यादेश में जमीन के मालिकों की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। भूमि अधिग्रहण से किसे, कैसे और कितना नुकसान हुआ और होने वाला है, इस सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए ग्राम सभा, जनसुनवाई आदि का कोई प्रावधान नहीं है। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में किसान व खेत मजदूर विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2015 की कड़ी भर्त्सना करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। साथ ही वाम नेताओं ने आम जनों से, खासकर किसान व खेत मजदूरों से इस जनविरोधी अध्यादेश के खिलाफ ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

महाधरना को एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य अरूण कुमार सिंह, ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन के रामाधीन सिंह, कृष्णदेव साह समेत अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार राज्य किसान सभा, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन, बिहार राज्य किसान सभा, बिहार राज्य किसान सभा (जमाल रोड), बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन, अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा, सीपीआई(एमएल), ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा, प्रगतिशील किसान सभा, बिहार राज्य गन्ना किसान सभा, एमसीपीआई(यू), अखिल भारतीय जनवादी किसान सभा के नेताओं ने संबोधित किया। महाधरना की अध्यक्षता ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन के राज्य अध्यक्ष शिव शंकर, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान तथा बिहार राज्य किसान सभा (जमाल रोड) के अध्यक्ष ललन चौधरी को लेकर गठित अध्यक्षमंडल ने की।

भीगे गेहूँ के समर्थन मूल्य में की गई कटौती का विरोध

रोहतक (हरियाणा): एस.यू.सी.आई.(सी) के हरियाणा राज्य सचिव कॉ. सत्यवान और कृषक खेत मजदूर संगठन के प्रदेश प्रधान कॉ. अनूप सिंह मातनहेल ने 18 अप्रैल को एक साझा बयान जारी किया। इसमें उन्होंने बारिश से भीगे गेहूँ के समर्थन मूल्य में रुपये 14.50 प्रति कुंतल की कटौती करने के मोदी सरकार के फरमान की कड़ी निन्दा की और इसे तत्काल वापस लेने, प्रति कुंतल 300 रुपये बोनस मूल्य देने और छोटे व गरीब किसानों के तमाम कर्जे समाप्त करने की मांग की। दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार के किसान-विरोधी इस फरमान के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रदेश के किसानों का आह्वान किया।

'साईंस फॉर मैनकाइण्ड' विषय पर सेमिनार

पिलानी(राजस्थान) : 15 अप्रैल को पिलानी में बीकेबीआईईटी में ब्रेकथ्रू साईंस सोसाइटी द्वारा 'साईंस फॉर मैनकाइण्ड' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य वक्ता ब्रेकथ्रू साईंस सोसाईटी के ऑल इण्डिया एक्जिक्यूटिव मेम्बर चंचल घोष ने विज्ञान का मानवता के लिए उपयोग पर चर्चा की। कार्यक्रम में ब्रेकथ्रू साईंस सोसाइटी के राजस्थान इंचार्ज राजमल शर्मा ने भी विज्ञान के बारे में विचार रखे।

कार्यक्रम का संचालन दीपक दहिया ने किया। कार्यक्रम के लिए बीकेबीआईईटी के डायरेक्टर श्री भटनागर ने सभी का धन्यवाद किया।

सही दिशा में एक जोरदार आन्दोलन का निर्माण करें

——— कॉमरेड कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

7 अप्रैल को जंतर मंतर, नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे देश के बिजली उपभोक्ताओं को सम्बोधित करते हुए ए. आई.यू.टी.यू.सी. के अध्यक्ष कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने कहा, आपने बहुत ही जरूरी और जायज मांग लेकर लड़ाई शुरू की है लेकिन यह लड़ाई कितनी कठिन है इसे आपको समझना चाहिए, इसमें हतोत्साहित होने की बात नहीं है। आपने कुछ प्रदर्शन कर दिये, कुछ धरने दिये, यहाँ तक कि जेल भर दी तब भी ऐसा नहीं लगता कि आप की मांग पूरी हो जाएगी। देश की जितनी भी बड़ी–बड़ी ट्रेड यूनियनें हैं, वे सभी मिलकर कई वर्षों से लड़ाई लड़ती आ रही हैं। 10 सूत्री मांगपत्र को लेकर हम लड़ रहे हैं लेकिन सरकार परवाह ही नहीं करती है। बिल्कुल परवाह नहीं करती है। सभी जानते हैं कि हमने लगातार दो दिन की हड़ताल की लेकिन सरकार परवाह नहीं करती है। बात ऐसी नहीं है कि आपने कोई एक प्रदर्शन या सम्मेलन कर लिया और सरकार आपकी मांग मान लेगी? बल्कि मैं यह कहूँगा कि जायज बात को सरकार मानती ही नहीं है। ऐसा हो गया है सरकार का रवैया। मांगें मनवानी होंगी यह आपको समझना चाहिए। सरकार मान लेगी इस उम्मीद से यदि आप आन्दोलन करें, अनुरोध करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें, कुछ भी करें, तो मैं कहूँगा आप समझे ही नहीं।

आजादी के तुरन्त बाद की स्थिति में ये टाटा–बिड़ला–गोयंका, आदि उस जमाने में अम्बानी–अदानी इतने बड़े पूंजीपति नहीं थे। बड़े–बड़े मूलभूत उद्योग जो आप देखते हो, ये लोग अपने पैसे से बना नहीं सकते थे। राऊरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो की स्टील इण्डस्ट्रीज, बीईएल, एचईएल, एचएएम, एचएमटी, इण्डियन टेलीकॉम इण्डस्ट्री इत्यादि ये कैसे लगी? जनता के पैसे से लगी थी। आप जानते हैं कि उस समय दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ था साम्राज्यवादी खेमा जिसे हम युद्ध खेमा कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ था समाजवादी शान्ति खेमा जिसका नेतृत्व पहले सोवियत संघ ने किया और बाद में चीन ने किया था। इन दो हिस्सों में दुनिया बंटी हुई थी। बड़े खेद की बात है महान स्तालिन की मृत्यु के बाद सोवियत रूस में ख्रुश्चेव नेतृत्व में आया और वहां संशोधनवादी लाइन लागू कर दी तब भी क्योंकि मूलतः समाजवादी खेमा ही था, रूस ने पिछड़े देशों को बराबर मदद दी। इसी के मुकाबले में अमेरिका, इंग्लैण्ड और फ्रांस ने भी चाहा कि वे भी मदद देकर इन पिछड़े मुल्कों को अपनी तरफ खींच लें। जो नव स्वाधीन देश थे जैसे कि भारत, बर्मा, इण्डोनेशिया, मिस्र आदि, वे दोनों खेमों में से किसी की भी तरफ नहीं गए। बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए बीच में रहे और दोनों गायों से दूध दूहते हुए भारतीय पूंजी की बाल्टी भरी। जो भी मूलभूत भारी उद्योग हैं, वे सब जनता के पैसे से और इन दोनों खेमों की मदद से लगाए गये हैं। जिन पर पल कर ये एकाधिकारी पूँजीपति टाटा, बिड़ला, गोयंका इतने बड़े हो गये कि टाटा आज इंग्लैण्ड की स्टील इण्डस्ट्री खरीदता है। जिस कच्चे माल की इन नए उद्योगों को जरूरत थी, उसे विदेश से खरीद कर ये विदेशी पूंजी के साथ होड़ नहीं कर सकते थे। सरकार ने जनता के पैसे से उनके लिए ये उद्योग लगा दिये और वे आराम से, बिजनैस करके जनता का शोषण करते–करते आज खरबपति बन गए। उन दिनों भारत के चारों तरफ टैरिफ वाल थी यानी बाहर से कोई भी माल खरीद कर लाओ तो आपको भारी शुल्क अदा करना पड़ता था जो न्यूनतम 300% था। इसलिए बाहर से आप खरीद नहीं सकते थे। उन दिनों उनका नारा ही था भारतीय बनो, भारतीय खरीदो। इस तरह भारत के इस विशाल बाजार का दोहन करके भारतीय एकाधिकारी घराने अमीर से अमीर बने। इसके फलस्वरूप लोग गरीब से गरीब होते गए। इसलिए आम लोग कहते थे कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब हुआ जबकि अमीर और भी अमीर हुआ।

लेकिन संशोधनवाद लागू हो जाने से सोवियत संघ में और उसके बाद चीन में भी प्रतिक्रान्ति हो गई। पूँजीवाद पुनर्स्थापित हो गया और दुनिया का चेहरा ही बदल गया। भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की यह जो नीति आप देख रहे हो, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अफ्रीकी–एशियाई उपनिवेश और अर्ध–उपनिवेश एक के बाद एक जब मुक्त होने लगे, तब यह सारा बाजार जो सीधे उनके हाथ में था, उसे खोने लगे। तभी से वे सोच रहे थे कि पुनः इन बाजारों में कैसे घुसपैठ की जाए, इसीलिए वे नव उपनिवेशवाद की नीति का अनुसरण कर रहे थे। नव उपनिवेशवाद का मतलब है तमाम औपनिवेशिक नीतियों को लागू करना लेकिन सीधे उपनिवेश बना कर नहीं। सीधे अपने अधीन रखना क्योंकि संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने नव–औपनिवेशिक नीति अपनाई। लेकिन उस समय वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि सोवियत संघ न केवल एक शान्ति खेमा था बल्कि एक समाजवादी बाजार भी था। विदेशी पूँजीवादी बाजार के पास जाने की इनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसीलिए इस गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने उस जमाने में अपनायी थी। उन्हीं दिनों साम्राज्यवादियों ने गैट (जनरल एग्रीमेण्ट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ) बनाया था लेकिन उसे लागू करने में कामयाब नहीं हो पाये थे। जब संशोधनवादी षड्यंत्र के चलते समाजवादी खेमा ढह गया तब यह भूमण्डलीकरण आया। 1991 में भूमण्डलीकरण की जो यह जनविरोधी नीति आई उसका मतलब क्या है? बड़े–बड़े साम्राज्यवादी देश जिनका बाजार खत्म हो रहा था क्योंकि समाजवादी देशों का जो बहुत बड़ा बाजार था उनके हाथ से निकल गया था और जितने देश उनके सीधे उपनिवेश थे, वे भी उनके हाथ से निकल गए थे। फिर उनके हाथ में बचा क्या? जबकि तकनीकी विकास की वजह से उत्पादन बढ़ने लगा था। यदि संशोधनवाद विकसित नहीं होता तो पूंजीवाद–साम्राज्यवाद मरने के रास्ते पर था। यदि स्टालिन का नेतृत्व बचा रहता तो ये सारी दुनिया आज लाल हो जाती। खैर, जो भी हो, दुख की बात है लेकिन हो गया उल्टा। पूँजीवादी–साम्राज्यवादी देश गैट को ही भूमण्डलीकरण के नाम पर नई नीति के रूप में लाए। भूमण्डलीकरण का मतलब बेरोकटोक हमारे देश की पूँजी किसी भी देश में जाएगी, दूसरों की हमारे देश में आएगी। उनका नारा था टैरिफ दीवार को खत्म करो। ऐसी टैरिफ वाल नहीं चलेगी। सब ने मान लिया। भारतीय पूँजीपतियों ने भी मान लिया। ऐसा नहीं है कि भारतीय पूँजीपति पर यह थोप दिया गया। भारतीय पूँजीपति वर्ग इस षड्यंत्र का एक हिस्सा ही रहा है जिसमें भूमण्डलीकरण की इस नीति को अपनाया गया। तभी से यह निजीकरण आया। जनता के पैसे से लगे उद्योग सार्वजनिक उद्योग के नाम से चलते थे। वह समाजवाद नहीं था। नेहरूजी ने दुनिया को यह कहा कि यह जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह समाजवाद भी है और पूँजीवाद भी। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद होता है जहाँ जो मजदूर हैं वे उत्पादन के साधनों के मालिक भी होते हैं और उत्पादन के साधनों के मालिक हैं वे मजदूर भी होते हैं और उत्पादन के वितरण को नियंत्रित भी वही करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं तो सार्वजनिक उद्योगों को भारतीय पूँजीवादी राजसत्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसको हम कहते हैं राजकीय पूँजीवाद, जिसे नेहरूजी ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बता कर दुनिया को धोखा देने का प्रयास किया। हमने भी धोखा खाया। लेकिन यहाँ समाजवादी किस्म का ढांचा जैसा कुछ था नहीं। यह जो सार्वजनिक क्षेत्र जनता के पैसे से तैयार हुआ था आज उसका निजीकरण किया जा रहा है। एक–एक उद्योगपति अब इतना बड़ा हो गया है कि वह बड़े–बड़े उद्योगों को खरीद सकता है और सरकार भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को इनके हवाले कर रही है। यह सरकार किसकी है? यह भी आपको समझना चाहिए। भूमण्डलीकरण की यह नीति कौन लाया? 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव लाये, डॉ. मनमोहन सिंह उस समय वित्तमंत्री थे। वाजपेयी के राज में जब यह बिजली कानून 2003 आया तो उन्होंने क्या भूमण्डलीकरण, उदीरीकरण और निजीकरण की नीतियों को छोड़ दिया था? नहीं, बल्कि और भी तेजी से लागू किया था। क्योंकि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, नीतियाँ नहीं बदलती हैं। जब देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार थी तो क्या भूमण्डलीकरण की नीति चली गई थी? बिलकुल नहीं। क्योंकि ये नीतियाँ सत्ताधारी वर्ग, पूँजीपति वर्ग की नीतियाँ हैं। यह आपको समझना चाहिए। जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे इनको मान कर ही चलना है, इनको लागू करना है और यदि वह इन्हें लागू न करे तो पूँजीपति कान पकड़ कर उसे निकाल देंगे। ये पूँजीपति वर्ग की नीतियाँ हैं। उसकी हर सरकार द्वारा लागू की जाती हैं। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, ये किसकी पाटियाँ हैं? दोनों ही पूँजीपति वर्ग की पाटियाँ हैं। यह बात यदि साफ न हो तो आप आन्दोलन करके कुछ नहीं कर पाओगे। आपका दुश्मन कौन है कांग्रेस या बीजेपी? ऐसा नहीं है, बल्कि वह है भारत का शासक वर्ग। जब कांग्रेस उसकी नीतियों को लागू करती है तब हमें कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ता है और जब बीजेपी सत्ता में होती है तब हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़ता है लेकिन मूल में तो ये पूँजीपति वर्ग, शासक वर्ग की नीतियाँ हैं। यह हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए।

आप आन्दोलन कर रहे हो बहुत अच्छा है। आप एक रास्ता दिखा रहे हो लेकिन आपको समझना चाहिए कि इतनी–सी ताकत से आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरे देश को आपको समझाना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि यह समस्या सिर्फ बंगाल, बिहार की है, बल्कि पूरे देश में पॉवर सैक्टर यानी बिजली क्षेत्र के निजीकरण की वही समस्या है। मध्य प्रदेश में जाएं, गुजरात में जाएं, सभी जगह यही है स्थिति। नरेन्द्र मोदी को सत्ता में कौन लाया। लाए ये कॉरपोरेट घराने– टाटा, अम्बानी, अदानी, ये सब। इस बार तो साफ दिखाई दिया, कुछ छिपा नहीं रहा कि ये लोग ही मोदी को लाये हैं। क्यों मोदी को लाये हैं? ऐसे तो जनविरोधी नीतियाँ अपनाते–अपनाते कांग्रेस बेहद अलोकप्रिय हो गई थी। इसके अलावा भ्रष्टाचार की दलदल में डूबते–डूबते कहाँ चली गई थी। कैसा भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार ने इतना भयंकर रूप लिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यह अन्ना हजारे आन्दोलन से पता चला। अन्ना हजारे का कोई संगठन नहीं था। हजारों लाखों लोग इस आन्दोलन में शामिल हुए। क्योंकि एक भी ईमानदार आदमी, ऐसा ईमानदार नेता उन्हें नजर जो नहीं आया। ऐसी कोई बुर्जुआ पार्टी भी नहीं है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। सारे ही भ्रष्ट हैं, नहीं तो अवसरवादी हैं, यहाँ तक कि वामपंथी पार्टियों ने भी अवसरवादी आचरण किया। इसी स्थिति में इतना बड़ा आन्दोलन, अन्ना हजारे का आन्दोलन हुआ। लोगों में आन्दोलन की यह जो चाह है, आन्दोलन के लिए जो मनोभाव देश भर में है, इसी से जनता इसमें शामिल हो जाती है। जहाँ पानी इतनी बहुतायत में है कि पानी बहते–बहते समुद्र में गिरता रहता है, वहाँ आपको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। सब कुछ का निजीकरण किया जा रहा है। कौन–सी चीज है जो प्राइवेट नहीं है। सभी क्षेत्रों में निजीकरण हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण हो रहा है। यदि निजीकरण की नीति को जन आन्दोलन के दबाव से परास्त नहीं कर सके तो बिजली क्षेत्र के निजीकरण को समाप्त करना कठिन है, असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन जरूर है। केजरीवाल ने बिजली–पानी में कुछ सब्सीडी दी है। सब्सीडी क्या होती है? केजरीवाल क्या अपनी जेब से देंगे? लोगों का पैसा उससे देंगे। मतलब क्या है? पॉवर सैक्टर में यदि सब्सिडी देते हैं तो विकास की दूसरी स्कीमों को बन्द करना पड़ेगा। हमने यह नहीं कहा कि सब्सिडी दो। हमने कहा कि यह सब्सीडी दे क्यों कर रहे हो? कम्पनियों ने जो दाम तय किया उसे ही रखा और उसे पैसा दे रहे हो। सब्सीडी दे रहे हो जनता के पैसे से। बंगाल में एक कहावत है मछली के तेल से मछली फ्राई करना। यह ऐसा ही है और कुछ नहीं। लोगों के पैसे से लोगों को सब्सीडी दो – यह हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है निजीकरण बन्द करो और बिजली दरों को कम करो, वह भी उत्पादन लागत के स्तर तक। सरकार मुनाफा न कमाए। सरकार किसानों सहित सभी को बिजली मुहैया कराए। बिजली एक बुनियादी जरूरत है। कॉमरेड नरेन्द्र शर्मा ने लेनिन को उद्धृत किया जो सही है। लेनिन का नारा ही था। जब क्रान्ति हुई तब रूस बहुत पिछड़ा हुआ था। उन्होंने कहा था कि विद्युतीकरण समाजवाद है। उन्होंने इसकी समाजवाद के साथ बराबरी की। बिजली ही तो समाज का आधुनिकीकरण कर सकती है। इसके बिना कैसे चलेगा और उसे आप निजी हाथों में सौंप रहे हो। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण किया जा रहा है। सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसलिए आन्दोलन यदि आप निजीकरण के खिलाफ कर सको, तभी आप जीत पाओगे। हम चाहेंगे आप जीतो। और जीत के लिए मैं कहूँगा कि आप निजीकरण की नीति को समझने का प्रयास करो। यह समझो कि पूँजीपति वर्ग, शासक वर्ग नरेन्द्र मोदी को लाया क्यों? (शेष पृष्ठ 8 पर)

क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम..

(पृष्ठ 4 का शेष)

सही रास्ते पर संचालित करने का सवाल एस.यू.सी.आई.(सी) को मजबूत करने के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को इसके बारे में संदेह नही रहना चाहिए। हमारे दुश्मन हमारी ताकत में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, वे इसके बारे में चौकस हैं और विभिन्न रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। बांकुड़ा में के.के.एम.एफ. कांफ्रेंस के प्रतिनिधि अधिवेशन में इसके बारे में मैंने आप लोगों को आगाह किया था। लेकिन हमारे बहुत से कॉमरेड इसके बारे में चौकस नहीं हैं। हमें कॉमरेडों को पर्याप्त रूप से लैस करना है ताकि वे वर्तमान स्थिति का भरपूर लाभ उठा सकें। इसके लिए जिन बिन्दुओं पर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, वे चर्चाओं के माध्यम से कॉमरेडों को समझाने होंगे। नेताओं को कॉमरेडों के साथ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बिन्दुओं पर चर्चा करने की आदत डालनी चाहिए ताकि यह उनकी भ्रान्ति को दूर करने, उनके चिन्तन में स्पष्टता लाने में सहायक हो सके और उनके उत्साह को बढ़ा सके। जिन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को नेतागण जानते हैं, उन्हें कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना चाहिए, सिर्फ स्टडी क्लासों में ही नहीं बल्कि बातचीत व गपशप के रूप में, अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से भी, यहाँ तक कि कानाफूसी अभियान के माध्यम से भी। लेकिन नेतागण अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं। वास्तविकता यह है कि सरकारी इंटेलिजेंस, केन्द्र और राज्य सरकारों, पुलिस और प्रशासन द्वारा जितनी हम पर निगरानी रखी जा रही है उतनी दूसरी विरोधी पार्टियों पर नहीं रखी जाती है। दूसरी विरोधी पार्टियों के प्रति वैमनस्य और हमारे प्रति वैमनस्य के चरित्र में फर्क है। जो कोई भी जन आन्दोलन संचालित करता है, या प्रशासन से जिसका वास्ता पड़ता है, यदि उसका राजनैतिक दृष्टिकोण है, तो दोनों के बीच फर्क को आसानी से समझ सकता है। दूसरी पार्टियाँ मुठभेड़ों और रक्तपात में लिप्त होती हैं, लेकिन तब भी उनके प्रति भावना व नजरिया जो उच्च स्तर पर, उच्चतम बुर्जुआ गोष्ठी के बीच काम करता है, हमारे प्रति अख्तियार किए जाने वाले रवैये से बिल्कुल भिन्न है। हमारे मामले में वर्ग शत्रुता प्रतिबिंबित होती है। किसी जगह एक अफसर कुछ वामपंथी रुझान वाला हो सकता है और हमारे कैडरों के आचरण की वजह से हमारी राजनीति के प्रति आकर्षित हो सकता है तथा एक विछिन्न उदाहरण के रूप में हमारे प्रति सहानुभूतिपूर्ण नजरिया रख सकता है। लेकिन देखा जाएगा कि उसको तुरन्त स्थानांतरित कर दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार जानती है कि एस.यू.सी.आई.(सी) अभी एक छोटी ताकत है लेकिन उन्होंने इतिहास से यह सीख ले ली है कि यदि एक क्रान्तिकारी पार्टी आज आकार में छोटी हो तो भी इसे नजरअंदांज नहीं करना चाहिए। एक पार्टी जिसके पास कहने लायक नामी नेता और प्रैस में प्रचार पब्लिसिटी भी नहीं हैं, जिसकी उपेक्षा की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है और हर कदम पर बाधा पहुँचाई जाती है, उसने जनता के आंकलन में महत्व हासिल किया है और इसके तथा इसके नेतृत्व के प्रति आकर्षण बढ़ा है–एक सत्य है जिसे अब वे नकार नहीं सकते हैं। मीडिया द्वारा लगभग पूर्ण ब्लैकआऊट के बावजूद भी इसके सिद्धान्तों और राजनीति के प्रसार को रोका नहीं जा सका है। यह पार्टी मीडिया प्रचार के बिना भी जनता तक पहुँच रही है।

इसलिए वे सोच रहे हैं कि जब एस.यू.सी.आई.(सी) ने लगभग शून्य से शुरू करके अपने इस वर्तमान स्तर को पा लिया है तब इसे और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पार्टी और ज्यादा नहीं बढ़े। शासक बुर्जुआ वर्ग और सरकार का नजरिया है कि एस.यू.सी.आई.(सी) को शुरूआत में ही खत्म कर दो। वे मानते हैं कि पूँजीवाद के लिए सी.पी.आई.(एम) या नक्सलवादी नहीं, बल्कि यही वह शक्ति है जिससे असल खतरा है। वे महसूस करते हैं कि इन दोनों को तो वे अपने तरीके से संभाल सकते हैं। वे सोचते हैं : एस.यू.सी.आई.(सी) जिस राजनीति और रणकौशलगत लाइन का अनुसरण करती है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। एस.यू.सी.आई.(सी) को उग्रपंथी कह कर बदनाम नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अभी भी जनवादी आन्दोलनों में शिरकत करती है। जनवादी आन्दोलनों में दूसरी पार्टियों के गर्मागर्म भाषणों और जुझारूपन के बावजूद उनके तौर-तरीके देख कर ही हम उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। वे हमारी पसंद के अनुरूप 'डेमोक्रेट' हैं जिनको हम संभाल सकते हैं, लेकिन हम एस.यू.सी.आई.(सी) को नहीं समझ पाते हैं। वे हूबहू वैसे 'डेमोक्रेट' नहीं हैं। वे अलग तरह के हैं। उनका बोलने का ढंग, काम करने का तरीका और उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग है–एस.यू.सी.आई.(सी) नेताओं और कार्यकर्ताओं का व्यवहार और तौर-तरीका भिन्न है'' बुर्जुआ वर्ग इसी प्रकार सोचता है। इसी वजह से वे चाहते हैं : या तो आप हमारी तरफ आ जाओ, दूसरी पार्टियों के नेताओं जैसे बन जाओ, उनकी तरह जायदाद और मकान हासिल करो, उनकी तरह भाषणबाजी में लिप्त रहो, कोई हर्ज नहीं यदि भाषण सरकार या पूँजीपतियों के खिलाफ हैं–लेकिन वैसे ही बन जाओ जैसा हम तुम्हें चाहते हैं; वरना तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तुम अलग चरित्र के हो।'' यही वजह है कि दुश्मन हमारे बारे में चौकस है, पुलिस का नजरिया भी हमारे बारे में बिलकुल भिन्न है। अपने बांकुड़ा के भाषण में मैंने इस बिन्दु को काफी स्पष्ट किया था। चुनाव लड़ाई में कांग्रेस और सी.पी.आई.(एम) के बीच आपसी विरोध का चरित्र भिन्न है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मैदान में सी.पी.आई.(एम), कांग्रेस की मुख्य शत्रु है। औद्योगिक घराने इन दोनों में से, कभी इसको और कभी उसको समर्थन देते रहते हैं। सांगठनिक क्षेत्र में उनके बीच खींचातानी है। ये सब सत्य है। लेकिन तब भी आप पाएंगे कि कांग्रेस जिस नजर से एस.यू.सी.आई.(सी) को देखती है उससे बिलकुल भिन्न नजर से सीपीआई(एम) को देखती है। जैसा कि वे एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। कांग्रेस जानती है कि चुनाव राजनीति में एस.यू.सी.आई.(सी) अभी भी एक बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन तब भी वे एस.यू.सी.आई को मुख्य शत्रु मानते हैं, क्योंकि क्रान्तिकारी पार्टी के रूप में एस.यू.सी.आई.(सी) उनकी मुख्य शत्रु है। प्रशासन हमारे प्रति बहुत कड़ा रुख अख्तियार करता है, लेकिन दूसरों के मामले में ऐसा नहीं करता है। दूसरे, सी.पी.आई.(एम) मार्क्सवाद का लबादा ओढ़कर जिस प्रकार लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है–एस.यू.सी.आई.(सी) उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। यही कारण है कि सी.पी.आई.(एम) एस.यू.सी.आई.(सी) को इतनी नफरत से देखती है। वे पाते हैं कि एस.यू.सी.आई.(सी) यद्यपि एक छोटी ताकत है, फिर भी इसे वे संयुक्त आन्दोलन में अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एस.यू.सी.आई.(सी) चुनावों में सीट हासिल करने या मंत्रिमण्डल में स्थान पाने के लालच में अपने सिद्धान्त, अपनी विचारधारा को छोड़ नहीं देती है; उनके द्वारा इतना कीचड़ उछालने के बावजूद भी एस.यू.सी.आई.(सी) के बारे मे जनता की रुचि बढ़ रही है, उनकी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी एस.यू.सी.आई.(सी) के बारे में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। इसलिए सी.पी.आई.(एम) जैसे भी हो एस.यू.सी.आई.(सी) को दरकिनार करना चाहती है। यहाँ सीपीआई(एम) कांग्रेस तथा दूसरी पार्टियों में उद्देश्य की समानता है। वोटों की खातिर उनके बीच जितना भी संघर्ष या प्रतिस्पर्धा हो, वे एसयूसीआई(सी) के खिलाफ गुट बना रहे हैं, कहीं-कहीं खुले तौर पर और कहीं-कहीं छिपे तौर पर, जहाँ कहीं भी यह पार्टी कुछ शक्ति अर्जित करती है। दूसरी छोटी पार्टियाँ भी हैं, वे भी पूँजीपतियों के साथ बातचीत करती हैं, वे पूँजीपतियों से सम्पर्क कर सकती हैं। लेकिन यह पार्टी पूँजीपतियों से कोई बात नहीं करती है, यह उनसे संपर्क नहीं साधती है। यह पार्टी फण्ड के लिए सड़कों पर बॉक्स कलैक्शन पर निर्भर करती है, किसानों, मजदूरों, आम आदमियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे पर निर्भर करती है। यह पार्टी फण्ड के लिए कभी भी पूँजीपतियों के पास नहीं जाती है। यही वह लक्षण है जिसमें पूँजीपतियों को खतरा नजर आता है। यदि उनको पता चलता है कि एक पार्टी उनसे सम्पर्क करती है, लेकिन साथ ही साथ क्रान्ति के बारे में बात करती है और इस ''क्रान्ति'' के लिए उनसे पैसे भी मांगती है तो उस पार्टी को वे अच्छी तरह समझ जाते हैं। ऐसे मामले में वे सोचते हैं: ''वे हमारे पास क्रान्ति के लिए आए और हमने उस क्रान्ति के लिए चन्दा दिया, यदि वे हमारे पैसों से क्रान्ति संगठित करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो।'' यदि यह घटता है तो वे निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन एसयूसीआई(सी) भिन्न चरित्र की पार्टी है। पूँजीपति हमें इस नजरिए से देखते हैं–''वे हमारे साथ कोई विशेष वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं; संघर्ष के हित में, समझौता-वार्ताओं में, वे हमसे बातचीत अवश्य करते हैं, लेकिन इनके अलावा वे हमसे कोई बातचीत नहीं करते हैं।'' यही वजह है कि उनकी नजरों में एस.यू.सी.आई.(सी) खतरनाक है। समाज के ऊँचे तबके के सुविधाभोगी लोग छोटी-बड़ी सभी दूसरी पार्टियों में हैं, लेकिन समाज के ये ऊँचे लोग एस.यू.सी.आई.(सी) के बीच में नहीं हैं। इसकी गतिविधियों का दायरा मजदूरों, गरीब किसानों, खेतिहर मजदूरों, निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के बीच है, इन तबकों के परिवारों से आए बेटे-बेटियों के बीच है। इसलिए इस पार्टी का चरित्र व व्यवहार पूँजीपतियों के लिए खतरनाक है। वे अपने ''डेमोक्रेटिक'' ढांचे में एक दूसरे तरह की पार्टियों की ही कामना करते हैं। इन्हीं वजहों से, वे हमारे बारे में बहुत चौकस हैं, यद्यपि अभी भी हम कोई बड़ी ताकत नहीं हैं। लेकिन हमारे बहुत से कार्यकर्ता हमारे दुश्मन की इस चौकसी के बारे में खुद चौकस नहीं हैं। वे इसके महत्त्व, अपनी जिम्मेदारी और अपनी ऐतिहासिक भूमिका को नहीं समझते हैं। इसी वजह से मैं जोर देता हूँ कि ये हमारी मूल कमजोरियाँ हैं। इनको दूर करने के लिए कार्यक्रम लेना ही इस विस्तारित राज्य कमेटी मीटिंग का उद्देश्य है। मैने इस विस्तारित बैठक में आपके सामने अपने विचार रखे हैं। आपने इनको सुना भी है। इसके बाद राज्य कमेटी या पदाधिकारी जरूरी कदमों पर फैसला लेने के लिए बैठेंगे। सभी जिला कमेटियों, लोकल कमेटियों और जन संगठन बॉडियों को तुरन्त अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहिए। प्रत्येक को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और काम के तरीके को सुधारने, पार्टी बॉडियों की जनवादी और राजनीतिक कार्यप्रणाली को सुधारने का प्रयास करना चाहिए; प्रत्येक को उसकी राजनीतिक चेतना और पहलकदमी बढ़ाने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए और प्रत्येक को व्याख्या करके यह बताना चाहिए कि कहाँ और कैसे वह पिछड़ रहा है; जब भी कभी हम पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलें दूसरी बातों के अलावा हमें पूछना चाहिए कि क्या वे जनसम्पर्क बना रहे हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के पास अपनी राजनीति को ले जा रहे हैं, कोई भी जो संगठित किया जा सकता है, उसको संगठित करने के लिए एक नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जन संगठनों को जहाँ कहीं भी और जिस तरीके से भी हो गठित करने में क्या वे पहलकदमी ले रहे हैं–चाहे वह एक क्लब या एक लाइब्रेरी, एक खेल गोष्ठी या जिमनाज़ियम, एक साहित्य-ड्रामा-संगीत सर्कल, एक कोचिंग क्लास या रात्रि स्कूल हो, क्या वे यह सब लोगों को एक साथ जुटा कर अपनी पहलकदमी से कर रहे हैं या वे खाली बैठ कर सर्कुलरों का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि दूसरों के द्वारा उनके लिए संपर्क बना दिए जाने हैं और आया कि वे सफल होंगे या नहीं इस प्रकार के फिजूल विचारों में समय बर्बाद करते हैं। पहलकदमी बढ़ाने और यदि गलतियाँ हो जाएं तब भी काम करते जाने का नजरिया होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना है, लेकिन माथे पे हाथ रख कर पश्चाताप में समय बर्बाद नहीं करना है कि ''आह! क्यों मैने गलती कर दी।'' इन सब की व्याख्या करनी है और कॉमरेडों को समझाना है। यह व्याख्या करनी है कि उन्हें विनम्र और सभ्य तरीके तथा व्यवहार से अपने चरित्र के गुण और ताकत से तर्क शक्ति के माध्यम से लोगों का दिल जीतना है। कार्यकर्ताओं को इस प्रकार शिक्षित करना है और इसके लिए जरूरी है, इनको लेकर संगठन के विभिन्न स्तरों पर गहन और व्यापक चर्चाएं चलाना, गलत सोच और विचारों, गलत और अनुचित पद्धति तथा काम के तरीके को दूर करने के लिए आन्दोलन का ज्वार पैदा करना।

आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ।

●●●

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing : 20 April, 2015

शिवसेना सांसद का बयान घोर साम्प्रदायिक

— एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट)

एस.यू.सी.आई.(सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 13 अप्रैल को जारी बयान में कहा कि शिवसेना के सांसद संजय राऊत ने जो यह घोर साम्प्रदायिक और भद्दी टिप्पणी की है कि वोट बैंक राजनीति को खत्म करने के लिए मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए उसकी हम कड़ी निन्दा करते हैं। राऊत जैसे धूर्त राजनीतिज्ञों की नितांत भड़काऊ और स्पष्ट रूप से अभिप्रेरित टिप्पणियाँ खुल्लमखुल्ला जनतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ जाती हैं, चुनने और चुने जाने के मूलभूत संवैधानिक अधिकार के लिए विध्वंसकारी हैं और जनतांत्रिक सिद्धांतों के बचे-खुचे अवशेषों को भी नष्ट कर देने के समान हैं। राऊत का गुस्ताख बयान हिन्दू कट्टरपंथी और रूढ़िवादी राजनीति का परिचायक है जिसे घोर प्रतिक्रियावादी आर.एस.एस.-शिव सेना-संघ परिवार बेखौफ हो कर आगे बढ़ा रहे हैं ताकि साम्प्रदायिक लाइन पर लोगों का ध्रुवीकरण करके चुनावी लाभ बटोरा जा सके और धार्मिक अंधता के आधार पर लोगों के बीच दरार पैदा की जा सके।

हम मांग करते हैं कि संजय राऊत की राज्य सभा की सदस्यता तुरंत रद्द की जाए। भारतीय नागरिकों के एक खास समुदाय के प्रति जानबूझकर घृणा और असंतोष फैला कर सामाजिक सद्भावना और देशवासियों के बीच भाईचारे को खतरे में डालने जैसे अक्षम्य अपराध करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

पौधों में जीवन की खोज के बारे में प्रधानमंत्री का दावा हास्यास्पद

— एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट)

7 अप्रैल 2015 को एस.यू.सी.आई.(सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी करते हुए कहा कि पौधों में जीवन के प्रमाण दिखाने के विश्वविख्यात आचार्य जगदीश चन्द्र बसु के जिस युगांतकारी आविष्कार को पूरी दुनिया श्रद्धा के साथ याद करती है उसको नकारने की धृष्टता भारत के प्रधान मंत्री ने दिखाई है। इससे पहले भी जिस प्रकार उन्होंने दावा किया था कि आधुनिक विमान संचालन विद्या, स्टैम सैल का उपयोग, ग्रह नक्षत्रों, की गतिविधियों इत्यादि के सम्बन्ध में सारा ज्ञान प्राचीन भारत में ही अर्जित हुआ था इसी की धारावाहिकता में ही इस बार मोदी का दावा है कि जगदीशचन्द्र बसु के आविष्कार के बहुत पहले सैकड़ों हजार वर्ष पूर्व गीता-महाभारत के समय ही भारतीय लोग जानते थे कि पौधों में जीवन है। इस तरह का मन्तव्य स्पष्ट तौर पर विज्ञान-विरोधी अर्थात् सच्चाई को विकृत करने वाला है।

इस विषय में कोई संदेह नहीं कि हिन्दुत्ववादी सिद्धान्त के प्रवक्ता नरेन्द्र मोदी इस घृणित वक्तव्य के जरिए हिन्दुत्ववादी साम्प्रदायिक कट्टरपंथी सिद्धान्त को ही देश के लोगों के बीच कायम करना चाहते हैं। उनका स्पष्ट उद्देश्य अज्ञानता, अंधकारपूर्ण भावना, परम्परावाद, तर्कहीनता और अंधउग्रता के बीज बोकर देश के लोगों के चिन्तन और चिन्तन प्रक्रिया को कुण्ठित कर देना है। जनता को इस प्रकार अज्ञानता के अंधकार में डूबो कर उसका लाभ उठाते हुए हिन्दुत्व के पैरोकार सत्ता के सिंहासन पर चढ़ना और उसे पुख्ता करना चाहते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए वे इतने बेपरवाह हैं कि उनका यह घृणित वक्तव्य जो उन प्रख्यात वैज्ञानिकों का अपमान है जिन पर भारत गर्व करता है इस बात को मानने से भी उन्हें एतराज है।

कॉमरेड चक्रवर्ती का भाषण...

(पृष्ठ 6 का शेष)

जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नन्दीग्राम-सिंगूर में जोरदार आन्दोलन हुए। सिंगूर में टाटा कम्पनी ने नैनो कार बनाने का कारखाना खोला और कहा कि 1 लाख में इसे देंगे। गरीब और मध्यम किसानों से बहुत सारी जमीन जबरन छीन कर बुद्धदेव सरकार ने टाटा को उपहार में दे दी। हमारी मांग थी कि कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। सिंगुर में आन्दोलन हमने शुरू किया था। ममता बैनर्जी बाद में इसमें आई थी। उस चुनाव क्षेत्र में उनका विधायक है। उनको आना पड़ा। जब कारखाने का निर्माणकार्य चल रहा था ममता बनर्जी उस आन्दोलन को कलकत्ता में ले गई। वहाँ जाकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तमाम मीडिया उधर चला गया। टाटा ने आराम से कारखाना बना लिया। हमने क्या यह मांग की थी कि आप कारखाना मत लगाओ? बिलकुल नहीं। कारखाना न लगाने की मांग तो लोगों ने उठाई ही नहीं थी। यह मांग की थी कि आपने जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया है उनको उचित मुआवजा दो। तब टाटा गुजरात क्यों भागे? इसलिए कि नरेन्द्र मोदी ने उनको सिंगूर से कई गुना ज्यादा जमीन दी, मुफ्त पानी दिया, मुफ्त बिजली दी, टैक्सों में छूट दी, ये सब सुविधाएं देने के अलावा उन्होंने वादा किया कि हम यहाँ मजदूर आन्दोलन की कतई इजाजत नहीं देंगे, कोई आन्दोलन करने नहीं देंगे। इससे टाटा बहुत खुश हुए। टाटा-अम्बानी-अदानी आदि सभी इस व्यक्ति से बहुत खुश हैं। क्योंकि यह आदमी उनके उद्योगों में मजदूर आन्दोलन होने नहीं देगा।

वे इस बार के चुनाव में उसको सामने लाये। कांग्रेस जब अलोकप्रिय हो गई तो नरेन्द्र मोदी को लाए। उनके लिए ये एकदम फिट आदमी है। मैं तो ये कहूँगा कि यह भी पूँजीपति वर्ग का संकट है कि इससे अच्छा आदमी उनको मिला ही नहीं। आपने सुना ही होगा, वे ऐसी बातें करते हैं कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी थी क्योंकि गणेशजी का सिर प्लास्टिक सर्जरी से लगाया गया था। इसके अलावा और भी ऐसी ऊटपटांग बातें वे करते हैं। इतने ज्ञानी आदमी? बड़ी-बड़ी बातें करते हैं इसलिए न सही, लेकिन ज्ञानी इस मायने में कि जनआन्दोलन को कैसे कुचला जाए, कैसे नरसंहार करवाया जाए और फिर हाथ धो लिया जाए। आज तक स्वीकार नहीं किया, न ही अफसोस ही जताया कि मैंने गलती की है। गर्भवती महिला का पेट चीरकर बच्चा निकाल कर त्रिशूल पर टांग कर नाचा बजरंग दल आर.एस.एस. और प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध करके भी सारे बरी हो गए। कह दिया कि नरेन्द्र मोदी भी उसमें शामिल नहीं था और अमित शाह भी नहीं। जबकि नानावती आयोग तब से जांच कर ही रहा है, पर कुछ निकला नहीं। तो यह है वह आदमी जिसे वे लाए है! इसलिए आप समझिए कि आज जो सत्ता में बैठा है और कल जो था उसमें कोई फर्क नहीं है चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, बल्कि बीजेपी और भी खतरनाक है। यह एक केन्द्रीकृत संगठन है, एक फासिस्ट संगठन है और इसके विचार बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इतना पुराना चिन्तन है कि 3-4 हजार साल पहले जो इन्सान सोचा-विचारा करते थे उसको वे महान मानते हैं जैसे, वैदिक साइन्स, वैदिक गणित। आज के गणित की तुलना में वैदिक गणित क्या है –यह आप सभी समझते हैं।

आज फासीवादी परिस्थिति है। पूरा एकदम फासीवाद आ गया हो जैसा कि हिटलर या मुसोलनी लाया था, वैसा नहीं है। पूर्णरूपेण फासीवाद लाने में समय लगेगा। जो राजसत्ता है वह फासीवादी हो गयी है। इसे अत्यंत केन्द्रीकृत, बहुत ही शक्तिशाली प्रशासनिक फासीवाद कहा जा सकता है।

अत: मैं कहूँगा, आपका आन्दोलन बहुत महान है लेकिन कठिन है, बहुत ही कठिन है–यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसका मायने है कि आपको पूरे देश के लोगों को समझाना होगा और इस आन्दोलन में लाना है। तभी यह देशव्यापी एकजुट आन्दोलन होगा। आप यदि प्रयास करो तो लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरा देश आन्दोलन के लिए बेताब है। हां, आपने आन्दोलन शुरू किया है, आन्दोलन की अगुआई की है, रास्ता दिखाया है लेकिन यही काफी नहीं है। सिर्फ इतने से ही आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक धरना-प्रदर्शन से ही अपनी मांगें नहीं मनवा सकते। आगे और लड़ाई है। इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं बार-बार कहूँगा कि आपका आन्दोलन महान है लेकिन बड़ा मुश्किल है। सही दिशा में एक जोरदार आन्दोलन का निर्माण करें। आप जरूर कामयाब होंगे। आप सभी का धन्यवाद।

एसयूसीआई(सी) ने की पुलिस बर्बरता की निन्दा

एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की आंध्र प्रदेश और तेलांगाना की सांगठनिक राज्य कमेटियों ने 7 अप्रैल की सुबह-सवेरे आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की राज्य पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में होने वाली मौतों की कड़ी निन्दा की।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर के सेशाचलम जंगलों में बीस लोग मारे गए। वे लकड़हारे कूली थे जिन्हें लाल-चन्दन के तस्करों ने मजदूरी पर रखा था। इन लकड़हारों को गिरफ्तार करके इनके जरिए जो इस तस्करी में शामिल है, उन तस्करों को ढूंढ़ने और सजा दिलाने के बजाए पुलिसवालों ने सभी लकड़हारों को जान से मार दिया।

उसी दिन नालगोण्डा जिले में अलेर के नजदीक तेलंगाना पुलिस के द्वारा उन पाँच संदिग्ध आतंकवादियों को जान से मार दिया गया जो न्यायिक हिरासत में थे। इन दोनों ही मुठभेड़ मौतों से कई सवालों उभर कर आ रहे हैं। एसयूसआई (कम्युनिस्ट) ने मांग की है कि प्रत्येक मुठभेड़ में होने वाली मौतों पर उच्च शक्तियां प्राप्त न्यायिक जांच बिठाई जाए, तथ्यों का पता लगाया जाए और साथ ही मृतकों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता दी जाए।

छात्र आन्दोलन की जीत

मुरादाबाद: 16 अप्रैल को ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की मुरादाबाद जिला कमेटी के नेतृत्व में एम.जे.पी. वि.वि. रूहेलखण्ड बरेली पर कुलसचिव कार्यालय के समक्ष एम.एच. कॉलेज, मुरादाबाद में ललित कला संकाय के आंतरिक परीक्षक डॉ. रवीश कुमार द्वारा उत्पीड़न तथा डॉ. संगीता गुप्ता द्वारा न पढ़ाए जाने के खिलाफ छात्रों द्वारा वि.वि. प्रशासन को बार-बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन के उपरान्त ए.आई.डी.एस.ओ. के नेतृत्व में छात्रों का एक प्रतिनिधिमण्डल कुलसचिव से मिला और इन दो मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा; एक डॉ. रवीश कुमार को आंतरिक परीक्षक के पद से तुरन्त हटाया जाए और दूसरा डॉ. संगीता गुप्ता को ललित कला संकाय से सेवामुक्त किया जाए। ज्ञापन पर वार्ता के दौरान कुलसचिव महोदय ने छात्रों की मांग को जायज माना और तत्काल

डॉ. रवीश को हटाकर अन्य परीक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए। इस प्रकार ए.आई.डी.एस.ओ. के नेतृत्व में छात्र आन्दोलन की जीत हुई और छात्रों का उत्पीड़न करने वाले शिक्षकों को सबक मिला। छात्र आन्दोलन की जीत पर ए.आई.डी.एस.ओ. की मुरादाबाद जिला अध्यक्ष कॉ. ऋतु चौधरी ने सभी छात्रों को बधाई दी और भविष्य में उत्पीड़न के विरोध में मजबूत छात्र आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान किया।

इस आन्दोलन का नेतृत्व मुरादाबाद जिला अध्यक्ष कॉ. ऋतु चौधरी और सचिव फैज खान, छात्र शाने आलम और तरुण गुप्ता ने किया।

"Print-line

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."